[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

लाइन से जुड़ जायेगा । यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर में गैस एवं पैट्रोल प्राप्ति की बड़ी संभावनायें हैं । जैसलमेर में तेल की खुदाई की कार्य चालू हो गया है ।

अत: केन्द्र सरकार के रक्षा एवं रेलवे मंत्रियों से निवेदन है कि देश की सुरक्षा एवं उन्नति के लिए पठानकोट से कांडला बड़ी लाइन के जल्दी से जल्दी सर्वेक्षण का कार्य शुरू कराकर उक्त रेलवे लाइन का कार्य युद्ध-स्तर पर शुरू करावें ताकि पिछड़े क्षेत्र भी दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले आ सकें ।

(iii) TEXTILE COMMISSIONER'S ORDER PROHIBITING SPINNING OF THREADS OF HIGH COURTS BY SMALL SPINNING MILLS IN TAMIL NADU

*SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM (Tirunelveli): Sir, under rule 377, I wish to raise the follwong matter of urbent public importance.

It is understood that the Textile Commissioner has recently issued a new order in contravention of the old order relating to Small Spinning Mills (Waste Cotton Mills). Under this new order, the small spinning (Waste-Cotton Mills) cannot spin in higher counts than 10 counts. Consequently, more than 250 scale industries have been brought to grief.

For these small spinning mills (Waste Cotton Mills), the required permission is given by the Textile Commissioner. The capacity of the machinery the counts of thread. The permission given by the Textile Commissioner is valid from 6 months to 2 years. Now, the small spinning mills have got suddenly this new order, according to which the permission given earlier for spinning higher counts lapsed on 31-3-82, since the in these Mills is the deciding factor for small spinning mills can spin only 10 counts.

In Tamil Nadu, all the small spinning mills (Waste Cotton Mills) have taken loans from the banks besides their own investments. There is the imminent danger of all of them becoming extinct. This will affect fore than 50,000 workers in these small spinning mills.

The Government of India should intervene immediately and annual the order of the Textile Commissioner in the interest of survival of small spinning mills (Waste Cotton Mills). They should be allowed to spin upto 40 counts. If this new order is allowed to continue, the prices of 20 counts and 40 counts thread will go up, affecting lakhs and lakhs of weavers.

(iv) GRANT OF SUBSIDY TO RAJASTHAN FARMERS FOR INCREASING PRODUCTION OF SOYABEAN

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तेल की कुल मांग के मुकाबले में उत्पादन की कमी के कारण मांग पूर्ति हेतु भारत सरकार को आयात पर निर्भर करना पड़ रहा है, जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ रही है । इसी को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों के लिए अनेक प्रेरणादायक निर्णय लिए हैं, जैसे सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसान को 650 रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान व उसके लिए 270 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य । इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर इस हेतु प्रयोगशालायें व अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं । गत वर्ष खरीफ में राजस्थान राज्य में विशेषकर चम्बल कमांड क्षेत्र में 13,000 हैक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन हुआ था तथा इस वर्ष में आगामी खरीफ के लिए राजस्थान के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सोयाबीन के उत्पादन हेतु 50,009 हेक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । परन्तु खेद है कि राजस्थान में सोयाबीन के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए किसी भी प्रकार का

*The original speech was delivered in Tamil